



भारत का राजपत्र

The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-01072024-255044
CG-DL-E-01072024-255044

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग I—खण्ड 1
PART I—Section 1

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 168]
No. 168]

नई दिल्ली, रविवार, जून 30, 2024/आषाढ 9, 1946
NEW DELHI, SUNDAY, JUNE 30, 2024/ASHADHA 9, 1946

वाणिज्य विभाग

(वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय)

(व्यापार उपचार महानिदेशालय)

जाँच शुरुआत अधिसूचना

नई दिल्ली, 29 जून, 2024

मामला सं - एडी (ओआई) - 16/2024

विषय : यूरोपीय संघ से किसी भी रूप में 'थिरम' के आयात के संबंध में एक पाटनरोधी जांच की शुरुआत।

फा.सं. 6/18/2024-डीजीटीआर.—स्वरूप केमिकल्स प्राइवेट लिमिटेड(जिन्हें यहां आगे "घरेलू उद्योग" अथवा "आवेदक" के रूप में भी कहा गया है) ने समय-समय पर यथासंशोधित सीमा शुल्क टैरिफ अधिनियम, 1975 (जिसे आगे "अधिनियम" के रूप में भी कहा गया है) और समय-समय पर यथा-संशोधित सीमा शुल्क टैरिफ (पाटित वस्तुओं की पहचान, उन पर पाटनरोधी शुल्क का आकलन और संग्रहण तथा क्षति का निर्धारण) नियमावली, 1995 (जिसे आगे "नियमावली" के रूप में भी कहा गया है) के अनुसार, निर्दिष्ट प्राधिकारी (जिन्हें आगे "प्राधिकारी" के रूप में भी कहा गया है) के समक्ष घरेलू उद्योग की ओर से एक आवेदन प्रस्तुत किया है जिसमें चीन जन. गण., पेरू और थाईलैंड (जिन्हें आगे "संबद्ध देश" के रूप में भी कहा गया है) के मूल के अथवा वहां से निर्यातित "एक्रिलिक फाइबर" के कथित पाटन के संबंध में पाटनरोधी जांच की शुरुआत करने का अनुरोध किया गया है।

2. आवेदक ने यह आरोप लगाया है कि संबद्ध देशों के मूल के अथवा वहां से निर्यातित विचाराधीन उत्पाद के पाटित आयातों के कारण घरेलू उद्योग को वास्तविक क्षति हो रही है और संबद्ध देशों से विचाराधीन उत्पाद के आयातों पर पाटनरोधी शुल्क लगाने का अनुरोध किया है।

क. विचाराधीन उत्पाद (पीयूसी)

3. वर्तमान जांच में विचाराधीन उत्पाद अपने तकनीकी और फॉर्मलेशन फॉर्म सहित किसी भी रूप में थिरम है।
4. थिरम का उपयोग खेत में फसल की क्षति को रोकने और भंडारण या परिवहन में फसलों को खराब होने से बचाने के लिए कवकनाशी के रूप में किया जाता है। थिरम का उपयोग विभिन्न प्रकार के फंगल रोगों से बीज, अखरोट, फल और मशरूम कीटाणुनाशक के रूप में भी किया जाता है। इसके अलावा, इसका उपयोग फलों के पेड़ों और सजावटी पौधों को खरगोशों, कृतकों और हिरणों से होने वाले नुकसान से बचाने के लिए पशु विकर्षक के रूप में किया जाता है। थिरम का उपयोग मानव खुजली के उपचार में, सनस्क्रीन के रूप में, और त्वचा पर सीधे लगाने या साबुन में मिलाने वाले जीवाणुनाशक के रूप में किया जाता है।
5. विचाराधीन उत्पाद को सीमा शुल्क टैरिफ अधिनियम, 1975 के अध्याय 38 के तहत टैरिफ वर्गीकरण के शीर्षक 3808 9230 के तहत वर्गीकृत किया गया है। विचाराधीन उत्पाद का एक समर्पित वर्गीकरण है। सीमा शुल्क वर्गीकरण केवल सांकेतिक है और यह जांच के दायरे पर बाध्यकारी नहीं है।
6. वर्तमान जांच के पक्ष विचाराधीन उत्पाद पर अपनी टिप्पणियाँ प्रदान कर सकते हैं और विषय जांच शुरू होने के 30 दिनों के भीतर पीसीएन (उचितिकरण के साथ), यदि कोई हो, प्रस्तावित कर सकते हैं। औचित्य और प्रासंगिक साक्ष्य के बिना की गई प्रस्तुतियों पर प्राधिकरण द्वारा विचार नहीं किया जा सकता है।

ख. समान वस्तु

7. आवेदक ने यह दावा किया है कि संबद्ध देशों से निर्यात की गई संबद्ध वस्तुओं और आवेदकों द्वारा उत्पादित वस्तुओं के बीच कोई ज्ञात अंतर नहीं है। आवेदक द्वारा उत्पादित तथा संबद्ध देशों से आयातित संबद्ध वस्तुएं, भौतिक और रासायनिक विशिष्टताओं, विनिर्माण प्रक्रिया और प्रौद्योगिकी, कार्यों और उपयोगों, उत्पाद विनिर्देशनों, मूल्य निर्धारण, वितरण और विपणन तथा वस्तुओं के टैरिफ वर्गीकरण जैसी आवश्यक उत्पाद विशिष्टताओं के संदर्भ में तुलनीय है। उपभोक्ता दोनों का परस्पर उपयोग करते हैं। आवेदक ने आगे दावा किया है कि दोनों ही तकनीकी और व्यावसायिक रूप में प्रतिस्थापनीय हैं, अतः उन्हें नियमों के तहत समान वस्तु के रूप में माना जाना चाहिए। अतः वर्तमान जांच के उद्देश्य से, आवेदक द्वारा उत्पादित उत्पाद को संबद्ध देशों से आयातित विचाराधीन उत्पाद के समान वस्तु के रूप में माना जा रहा है।

ग. संबद्ध देश

8. वर्तमान जांच में संबद्ध देश में यूरोपीय संघ हैं।

घ. जांच की अवधि (पी.ओ.आई.)

9. आवेदकों ने जांच की अवधि 1 जनवरी 2023 से 31 दिसंबर 2023 (12 महीने की अवधि) मानी है। क्षति सूचना अवधि में वित्तीय वर्ष 2020-21, 2021-22 और 2022-23 और जांच की अवधि शामिल है।

ड. घरेलू उद्योग और आधार

10. आवेदन स्वरूप केमिकल प्राइवेट लिमिटेड द्वारा दायर किया गया है। अंबा केम इंडस्ट्रीज की ओर से समर्थन पत्र दाखिल किया गया है। यह प्रस्तुत किया गया है कि सुदामा केमटेक प्रा. लिमिटेड भारत में उत्पाद का एक अन्य उत्पादक है।
11. उपलब्ध जानकारी के आधार पर, आवेदक का उत्पादन भारत में समान वस्तु के घरेलू उत्पादन का एक बड़ा हिस्सा है। इसके अलावा, आवेदक का संबद्ध देश में किसी निर्यातक या भारत में किसी आयातक से कोई संबंध नहीं है।
12. प्रदान की गई सूचना के आधार पर, यह देखा गया है कि आवेदक नियम 2(ख) के तात्पर्य से "घरेलू उद्योग" का गठन करते हैं और आवेदन नियम 5(3) के अनुसार आधार मानदंडों को पूरा करता है।

च. सामान्य मूल्य, निर्यात मूल्य और पाटना**सामान्य मूल्य**

13. आवेदक ने दावा किया है कि यूरोपीय संघ में घरेलू बाजार में उत्पाद की बिक्री मूल्य के संबंध में कोई प्रकाशित जानकारी नहीं है। आवेदक ने यह भी प्रस्तुत किया है कि उत्पाद की बिक्री पर यूरोपीय संघ में प्रतिबंध लगाए गए

हैं और इसलिए, यह स्पष्ट नहीं है कि यूरोपीय संघ के घरेलू बाजार में विचाराधीन उत्पाद की पर्याप्त बिक्री है या नहीं। इसलिए, आवेदक ने प्रशासनिक, बिक्री और सामान्य लागत और मुनाफे के लिए उचित वृद्धि के साथ उत्पादन की लागत के आधार पर सामान्य मूल्य का प्रस्ताव दिया है। जांच शुरू करने के लिए आवेदक द्वारा प्रस्तावित सामान्य मूल्य पर विचार किया गया है।

छ. निर्यात कीमत

14. आवेदक ने डीजीसीआईएंडएस द्वारा प्रकाशित आंकड़ों के अनुसार भारत में सीआईएफ आयात मूल्य को अपनाया है। हालाँकि, प्राधिकरण ने डीजी सिस्टम्स लेनदेन-वार डेटा पर विचार किया है। चूंकि जानकारी सीआईएफ के आधार पर है, इसलिए फैक्ट्री-पूर्व निर्यात मूल्य पर पहुंचने के लिए समुद्री माल ढुलाई, समुद्री बीमा, कमीशन, अंतर्देशीय माल ढुलाई, बंदरगाह व्यय और बैंक शुल्क के आधार पर समायोजन किया गया है।

ज. पाटन मार्जिन

15. ऊपर निर्धारित सामान्य मूल्य और निर्यात मूल्य को ध्यान में रखते हुए, पाटन मार्जिन निर्धारित किया गया है। यह नोट किया गया है कि पाटन मार्जिन महत्वपूर्ण है और न्यूनतम स्तर से ऊपर है। इस प्रकार, इस बात के पर्याप्त प्रथम दृष्टया सबूत हैं कि विचाराधीन उत्पाद का सामान्य मूल्य उस कीमत से अधिक है जिस पर इसे संबद्ध देश से निर्यात किया जाता है, इस प्रकार प्रथम दृष्टया साक्ष्य है कि विचाराधीन उत्पाद को संबद्ध देशों के निर्यातकों द्वारा भारतीय बाजार में पाटित किया जा रहा है।

झ. क्षति और कारणात्मक संबंध

16. आवेदक ने पाटित आयातों के कारण घरेलू उद्योग को हुई क्षति के संबंध में प्रथम दृष्टया साक्ष्य प्रदान किया है। क्षति के आकलन के लिए आवेदक द्वारा दी गई जानकारी पर विचार किया गया है। आवेदक ने कथित पाटन के कारण हुई क्षति के संबंध में प्रथम दृष्टया साक्ष्य प्रस्तुत किया है, जिसके परिणामस्वरूप महत्वपूर्ण नुकसान हुआ है। आवेदक ने दावा किया है कि मांग-आपूर्ति में कोई अंतर नहीं होने के बावजूद, संबद्ध आयात की मात्रा में वृद्धि हुई है। आवेदक काफी कम क्षमता उपयोग और बाजार हिस्सेदारी के साथ काम कर रहा है। आवेदक वित्तीय घाटे, नकदी घाटे और नियोजित पूंजी पर नकारात्मक रिटर्न के साथ काम कर रहा है। पाटनरोधी जांच की शुरुआत को उचित ठहराने के लिए विषयगत देश से विषयगत वस्तुओं के डंप किए गए आयात के कारण आवेदक को होने वाली भौतिक क्षति के पर्याप्त प्रथम दृष्टया सबूत हैं।

ञ. पाटनरोधी जांच की शुरुआत

17. आवेदक द्वारा विधिवत प्रमाणित लिखित आवेदन के आधार पर, और स्वयं संतुष्ट होने के बाद, विषय देश में उत्पन्न या वहां से निर्यात किए गए विचाराधीन उत्पाद की डंपिंग के बारे में प्रस्तुत प्रथम दृष्टया साक्ष्य के आधार पर, घरेलू उद्योग को नुकसान और इस तरह के कथित डंपिंग और क्षति के बीच कारण संबंध, और नियमों के नियम 5 के साथ पढ़े गए अधिनियम की धारा 9 ए के अनुसार, प्राधिकरण, इसके संबंध में किसी भी कथित डंपिंग के अस्तित्व, डिग्री और प्रभाव को निर्धारित करने के लिए एक जांच शुरू करता है। विषयगत देश में उत्पन्न या वहां से निर्यातित विचाराधीन उत्पाद और एंटी-डंपिंग शुल्क की राशि की सिफारिश करना, जो यदि लगाया जाता है, तो घरेलू उद्योग को होने वाली क्षति को दूर करने के लिए पर्याप्त होगा।

ट. प्रक्रिया

18. वर्तमान जांच के लिए नियमावली के नियम 6 में दिए गए सिद्धांतों का पालन किया जाएगा।

ठ. सूचना प्रस्तुत करना

19. निर्दिष्ट प्राधिकारी संचार ई-मेल पतों dir16-dgtr@gov.in और dd15-dgtr@gov.in जिसकी एक प्रति adg16-dgtr@gov.in और adv13-dgtr@gov.in पर ई-मेल के माध्यम से भेजे जाने चाहिए। यह सुनिश्चित किया जाना चाहिए कि अनुरोध का वर्णनात्मक हिस्सा पीडीएफ/ एमएस वर्ड फॉर्मेट में और आंकड़ों की फाइल एम एस एक्सल फॉर्मेट में खोजी जाने योग्य होनी चाहिए।
20. संबद्ध देश में ज्ञात उत्पादकों/ निर्यातकों, भारत में उनके दूतावास के जरिए संबद्ध देशों की सरकार, भारत में संबद्ध वस्तु से संबंधित समझे जाने वाले आयातकों और प्रयोक्ताओं को इस जांच शुरुआत की अधिसूचना में उल्लिखित समय सीमा के भीतर समस्त संगत सूचना प्रस्तुत करने के लिए अलग से सूचित किया जा रहा है। ऐसी

समस्त सूचना इस जांच शुरुआत की अधिसूचना, नियमावली और प्राधिकारी द्वारा जारी लागू व्यापार सूचनाओं में यथाविहित प्रपत्र और ढंग से प्रस्तुत की जानी चाहिए।

21. कोई अन्य हितबद्ध पक्षकार भी इस जांच शुरुआत की अधिसूचना, पाटनरोधी नियमावली, 1995 और प्राधिकारी द्वारा जारी लागू व्यापार सूचनाओं में यथा विहित प्रपत्र और ढंग से इस जांच शुरुआत अधिसूचना में उल्लिखित समय सीमा के भीतर वर्तमान जांच से संगत अपने अनुरोध प्रस्तुत कर सकता है।
22. प्राधिकारी के समक्ष कोई भी गोपनीय अनुरोध करने वाले किसी पक्षकार को अन्य हितबद्ध पक्षकारों को उपलब्ध कराने के लिए उसका एक अगोपनीय पाठ प्रस्तुत करना अपेक्षित है।
23. हितबद्ध पक्षकारों को यह भी सलाह दी जाती है कि वे जांच के संबंध में किसी अद्यतन जानकारी के लिए निर्दिष्ट प्राधिकारी की अधिकारिक वेबसाइट (<http://www.dgtr.gov.in/>) पर नियमित रूप से नजर रखें।

ड. समय सीमा

24. वर्तमान जांच से संबंधित कोई सूचना प्राधिकारी को नियमावली के नियम 6(4) के अनुसार घरेलू उद्योग द्वारा आवेदन के अगोपनीय पाठ को दाखिल किए जाने की तारीख से 30 दिनों के भीतर निर्दिष्ट प्राधिकारी द्वारा ई-मेल पत्तों dir16-dgtr@gov.in और dd15-dgtr@gov.in तथा उसकी प्रति adg16-dgtr@gov.in और adv13-dgtr@gov.in को ई-मेल के माध्यम से परिचालित की जाएगी अथवा निर्यातक देशों के उपयुक्त राजनायिक प्रतिनिधि को भेजी जाएगी। यदि विहित समय सीमा के भीतर कोई सूचना प्राप्त नहीं होती है या प्राप्त सूचना अधूरी होती है तो प्राधिकारी नियमावली के अनुसार रिकॉर्ड में उपलब्ध तथ्यों के आधार पर अपने जांच परिणाम दर्ज कर सकते हैं।
25. सभी हितबद्ध पक्षकारों को एतद्वारा सलाह दी जाती है कि वे वर्तमान मामले में अपने हित (हित के स्वरूप सहित) की सूचना दें और इस इस अधिसूचना में उक्त समय सीमा के भीतर प्रश्नावली का अपना उत्तर प्रस्तुत करें।
26. जहां कोई हितबद्ध पक्षकार अनुरोध प्रस्तुत करने के लिए अतिरिक्त समय मांगता है वहां उसे एडीडी नियमावली, 1995 के नियम 6(4) के अनुसार समय बढ़ाने का पर्याप्त कारण बताना होगा और वह अनुरोध इस अधिसूचना में निर्धारित समयावधि के भीतर किया जाना चाहिए।

ढ. गोपनीय आधार पर सूचना की प्रस्तुती

27. वर्तमान जांच में प्राधिकारी के समक्ष कोई गोपनीय अनुरोध करने या गोपनीय आधार पर सूचना प्रस्तुत करने वाले किसी पक्षकार को नियमावली के नियम 7(2) और इस संबंध में प्राधिकारी द्वारा जारी संगत व्यापार सूचनाओं के अनुसार ऐसी सूचना का अगोपनीय अंश भी साथ में प्रस्तुत करना अपेक्षित है।
28. ऐसी प्रस्तुतियों को प्रत्येक पृष्ठ के शीर्ष पर स्पष्ट रूप से "गोपनीय" या "अगोपनीय" के रूप में चिह्नित किया जाना चाहिए। ऐसे चिह्नों के बिना प्राधिकरण को किया गया कोई भी प्रस्तुतीकरण प्राधिकरण द्वारा "अगोपनीय" जानकारी के रूप में माना जाएगा, और प्राधिकरण अन्य इच्छुक पार्टियों को ऐसे प्रस्तुतीकरणों का निरीक्षण करने की अनुमति देने के लिए स्वतंत्र होगा।
29. इच्छुक पार्टियों द्वारा दायर की गई जानकारी का गैर-गोपनीय संस्करण अनिवार्य रूप से गोपनीय संस्करण की प्रतिकृति होना चाहिए, जिसमें गोपनीय जानकारी को अधिमानतः अनुक्रमित या खाली किया जाना चाहिए (जहां अनुक्रमण संभव नहीं है) और ऐसी जानकारी को उचित और पर्याप्त रूप से संक्षेप में प्रस्तुत किया जाना चाहिए। उस जानकारी पर जिस पर गोपनीयता का दावा किया गया है।
30. गोपनीय आधार पर दी गई जानकारी के सार को उचित ढंग से समझने के लिए गैर-गोपनीय सारांश पर्याप्त विवरण में होना चाहिए। हालांकि, असाधारण परिस्थितियों में, गोपनीय जानकारी प्रस्तुत करने वाली पार्टी यह संकेत दे सकती है कि ऐसी जानकारी सारांश के लिए अतिसंवेदनशील नहीं है, और नियमों, 1995 के नियम 7 और जारी किए गए उचित व्यापार नोटिस के संदर्भ में पर्याप्त और पर्याप्त स्पष्टीकरण वाले कारणों का विवरण शामिल है। प्राधिकरण द्वारा, ऐसा सारांश क्यों संभव नहीं है, प्राधिकरण की संतुष्टि के लिए प्रदान किया जाना चाहिए। अन्य इच्छुक पक्ष दस्तावेज़ का गैर-गोपनीय संस्करण प्राप्त होने के 7 दिनों के भीतर दावा की गई गोपनीयता पर अपनी टिप्पणियाँ दे सकते हैं।

31. गोपनीयता के दावे पर उसके सार्थक गैर-गोपनीय संस्करण के बिना या नियम, 1995 के नियम 7 और प्राधिकरण द्वारा जारी उचित व्यापार नोटिस के संदर्भ में पर्याप्त और पर्याप्त कारण विवरण के बिना किए गए किसी भी प्रस्तुतीकरण को प्राधिकरण द्वारा रिकॉर्ड पर नहीं लिया जाएगा।

ण. सार्वजनिक फाइल का निरीक्षण

32. पंजीकृत इच्छुक पार्टियों की एक सूची डीजीटीआर की वेबसाइट पर अपलोड की जाएगी और साथ ही उन सभी से अनुरोध किया जाएगा कि वे अन्य सभी इच्छुक पार्टियों को अपनी प्रस्तुतियों का गैर-गोपनीय संस्करण ईमेल करें। प्रस्तुतियाँ/प्रतिक्रिया/सूचना के गैर-गोपनीय संस्करण को प्रसारित करने में विफलता के कारण इच्छुक पैरी को असहयोगी माना जा सकता है।

त. असहयोग

33. यदि कोई हितबद्ध पक्षकार इस जांच शुरूआत अधिसूचना में प्राधिकारी द्वारा निर्धारित और अलग पत्र के जरिए दी गई आगामी समयावधि के भीतर आवश्यक सूचना जुटाने से मना करता है अथवा उसे अन्यथा उपलब्ध नहीं कराता है या जांच में अत्यधिक बाधा डालता है तो प्राधिकारी ऐसे हितबद्ध पक्षकार को असहयोगी घोषित कर सकते हैं और उपलब्धत थ्यों के आधार पर अपने जांच परिणाम दर्ज कर सकते हैं तथा केन्द्र सरकार को यथोचित सिफारिशें कर सकते हैं।

अनन्त स्वरूप, निर्दिष्ट प्राधिकारी

DEPARTMENT OF COMMERCE

(Ministry of Commerce and Industry)

(DIRECTORATE GENERAL OF TRADE REMEDIES)

INITIATION NOTIFICATION

New Delhi, the 29th June, 2024

Case No. AD (OI)-16/2024

Subject: Initiation of an anti-dumping investigation concerning the imports of 'Thiram in any form' from the European Union.

F. No. 6/18/2024-DGTR.—Swarup Chemicals Private Limited (hereinafter referred to as the "applicant") has filed an application before the Designated Authority (hereinafter referred to as the "Authority") in accordance with the Customs Tariff Act, 1975 as amended from time to time (hereinafter referred as the Act) and the Customs Tariff (Identification, Assessment and Collection of Anti-dumping Duty on Dumped Articles and for Determination of Injury) Rules, 1995, as amended from time to time (hereinafter referred to as the "Rules") for initiation of an anti-dumping investigation concerning the imports of Thiram in any form (hereafter referred to as the "subject goods" or the "product under consideration"), originating in or exported from the European Union (hereafter referred to as the "subject country").

2. The applicant has alleged that material injury is being caused to the applicant due to the dumped imports from the subject country and has requested for imposition of anti-dumping duty on the imports of the subject goods, originating in or exported from the subject country.

A. Product under consideration (PUC).

3. The product under consideration in the present investigation is Thiram in any form including its technical and formulation form.
4. Thiram is used as a fungicide to prevent crop damage in the field and to prevent crops from deterioration in storage or transport. Thiram is also used as a seed, nut, fruit, and mushroom disinfectant from a variety of fungal diseases. In addition, it is used as an animal repellent to protect fruit trees and ornamentals from damage by rabbits, rodents, and deer. Thiram has been used in the treatment of human scabies, as a sunscreen, and as a bactericide applied directly to the skin or incorporated into soap.
5. The product under consideration is classified under Chapter 38 of the Customs Tariff Act, 1975 under heading 3808 92 30 of the Tariff Classification. The product under consideration has a dedicated classification. The customs classification is only indicative and the same is not binding on the scope of the investigation.

6. The parties to the present investigation may provide their comments on the product under consideration and propose PCNs (with justification), if any, within 30 days of the initiation of the subject investigation. Submissions made without justification and relevant evidence may not be considered by the Authority.

B. Like article.

7. The applicant has claimed that the product produced by them is identical to the imported product. The product produced by the applicant is comparable to the imported goods from the subject country in terms of technical specifications, manufacturing process & technology, functions & uses, pricing, distribution & marketing and tariff classification of the goods. The two are technically and commercially substitutable and should be treated as like article under the rules. Therefore, for the purpose of the present investigation, the product produced by the applicant is being treated as like article to the product under consideration imported from the subject country.

C. Subject country.

8. The subject country in the present investigation is the European Union.

D. Period of investigation (POI).

9. The period of investigation (POI) for the present investigation is from 1st January 2023 to 1st December 2023 (a period of 12 months). The injury period for the investigation will cover the periods 2020-21, 2021-22 and 2022-23 and the period of investigation.

E. Domestic industry and standing.

10. The application has been filed by the Swarup Chemical Private Limited. Support letter has been filed by Amba Chem Industries. It has been submitted that Sudama Chemtech Pvt. Ltd is the one other producer of the product in India.
11. Based on the information available, the production of the applicant accounts for a major proportion of the domestic production of like article in India. Further, the applicant is not related to any exporters in the subject country nor to any importers in India.
12. In view of the above, the Authority *prima facie* considers that the applicant constitutes "domestic industry" within the meaning of Rule 2(b) of the Rules and the application satisfies the criteria of standing in terms of Rule 5(3) of the Rules.

F. Normal value, export price and dumping.

Normal value.

13. The applicant has claimed that there is no published information regarding the selling price of the product in the domestic market in the European Union. The applicant has also submitted that there are restrictions imposed in the European Union on the sale of the product and therefore, it is unclear if there are sufficient sales of the product under consideration in the domestic market of the European Union. The applicant has, therefore, proposed the normal value based on its cost of production with reasonable addition for administrative, selling & general costs and for profits. The normal value proposed by the applicant has been considered for initiation of the investigation.

Export Price

14. The applicant has adopted the CIF import price into India as reported by the DGCI&S published data. However, the Authority has considered DG Systems transaction-wise data. Since the information is on CIF basis, adjustments have been made on account of ocean freight, marine insurance, commission, inland freight, port expenses, and bank charges to arrive at ex-factory export price.

Dumping margin

15. Considering the normal value and the export price as determined above, the dumping margin has been determined. It is noted that the dumping margin is significant and above the *de minimis* level. Thus, there is sufficient *prima facie* evidence that the normal value for the product under consideration is higher than the price at which it is exported from the subject country indicating that the product originating or exported from the subject country is being dumped in the Indian market by the exporters.

G. Injury and causal link.

16. The information furnished by the applicant has been considered for the assessment of injury. The applicant has furnished *prima facie* evidence regarding the injury because of the alleged dumping, resulting in a significant loss. The applicant has claimed that despite no demand-supply gap, the volume of subject imports has increased. The applicant is operating with significantly low capacity utilization and market share. The applicant

is operating with financial losses, cash losses and a negative return on capital employed. There is sufficient *prima facie* evidence of material injury being caused to the applicant by the dumped imports of the subject goods from the subject country to justify the initiation of the anti-dumping investigation.

H. Initiation of anti-dumping investigation.

17. On the basis of the duly substantiated written application by the applicant, and having satisfied itself, on the basis of *prima facie* evidence submitted about the dumping of the product under consideration originating in or exported from the subject country, injury to the domestic industry and causal link between such alleged dumping and injury, and in accordance with Section 9A of the Act read with Rule 5 of the Rules, the Authority, hereby, initiates an investigation to determine the existence, degree and effect of any alleged dumping in respect of the product under consideration originating in or exported from the subject country and to recommend the amount of anti-dumping duty, which if levied, would be adequate to remove the injury to the domestic industry.

I. Procedure

18. Principles as given in Rule 6 of the Rules will be followed for the present investigation.

J. Submission of information

19. All communication should be sent to the Designated Authority via email at email addresses dir16-dgtr@gov.in and dd15-dgtr@gov.in and with a copy to adg16-dgtr@gov.in and adv13-dgtr@gov.in It must be ensured that the narrative part of the submission is in searchable PDF/MS Word format and data files are in MS Excel format.
20. The known producers/exporters in the subject country, the government of the subject country through its embassy in India, and the importers and users in India who are known to be associated with the subject goods are being informed separately to enable them to file all the relevant information within the time limits mentioned in this notification. All such information must be filed in the form and manner as prescribed by this initiation notification, the Rules, 1995 and the applicable trade notices issued by the Authority.
21. Any other interested party may also make a submission relevant to the present investigation in the form and manner as prescribed by this initiation notification, the Rules, 1995 and the applicable trade notices issued by the Authority within the time limit mentioned in this initiation notification.
22. Any party making any confidential submission before the Authority is required to make a non-confidential version of the same available to the other interested parties.
23. Interested parties are further advised to keep a regular watch on the official website of the Designated Authority <http://www.dgtr.gov.in/> for any updated information with respect to this investigation.

K. Time limit

24. Any information relating to the present investigation should be sent to the Designated Authority via email at email address- dir16-dgtr@gov.in and dd15-dgtr@gov.in and with a copy to adg16-dgtr@gov.in and adv13-dgtr@gov.in within 30 days from the date on which it was sent by the Designated Authority or transmitted to the appropriate diplomatic representative of the exporting country as per Rule 6(4) of the Rules. If no information is received within the stipulated time limit or the information received is incomplete, the Authority may record its findings on the basis of the facts available on record and in accordance with the Rules, 1995.
25. All the interested parties are hereby advised to register themselves in the subject investigation and file their questionnaire responses within the above time limit as stipulated in this notification.
26. Where an interested party seeks additional time for filing of submissions, it must demonstrate sufficient cause for such extension in terms of Rule 6 (4) of the Rules, 1995 and such request must come within the time stipulated in this notification.

L. Submission of information on confidential basis

27. Where any party to the present investigation makes confidential submissions or provides information on a confidential basis before the Authority, it is required to simultaneously submit a non-confidential version of such information in terms of Rule 7(2) of the Rules and in accordance with the relevant trade notices issued by the Authority in this regard.
28. Such submissions must be clearly marked as "confidential" or "non-confidential" at the top of each page. Any submission which has been made to the Authority without such markings shall be treated as "non-confidential" information by the Authority, and the Authority shall be at liberty to allow other interested parties to inspect such submissions.

29. The non-confidential version of the information filed by the interested parties should essentially be a replica of the confidential version with the confidential information preferably indexed or blanked out (where indexation is not possible) and such information must be appropriately and adequately summarized depending upon the information on which confidentiality is claimed.
30. The non-confidential summary must be in sufficient detail to permit a reasonable understanding of the substance of the information furnished on a confidential basis. However, in exceptional circumstances, the party submitting the confidential information may indicate that such information is not susceptible to a summary, and a statement of reasons containing a sufficient and adequate explanation in terms of Rule 7 of the Rules, 1995 and appropriate trade notices issued by the Authority, as to why such summarization is not possible, must be provided to the satisfaction of the Authority. The other interested parties can offer their comments on the confidentiality claimed within 7 days of receiving the non-confidential version of the document.
31. Any submission made without a meaningful non-confidential version thereof or without a sufficient and adequate cause statement in terms of Rule 7 of the Rules, 1995 and appropriate trade notices issued by the Authority, on the confidentiality claim shall not be taken on record by the Authority.

M. Inspection of public file

32. A list of registered interested parties will be uploaded on the DGTR's website along with the request therein to all of them to email the non-confidential version of their submissions to all other interested parties. Failure to circulate non-confidential version of submissions/response/ information might lead to consideration of an interested party as non-cooperative.

N. Non-cooperation

33. In case any interested party refuses access to and otherwise does not provide necessary information within a reasonable period or within the time stipulated by the Authority in this initiation notification, or significantly impedes the investigation, the Authority may declare such interested party as non-cooperative and record its findings on the basis of the facts available to it and make such recommendations to the Central Government as deemed fit.

ANANT SWARUP, Designated Authority